development of Poly Coir, comes to Rs. 9.98 lakhs.

No expenditure has so far been incurred on the technology upgradation of Coir Geo-fabrics.

Sick Textile Mills

787. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI VITHALBHAI M. PATEL:
SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to close down sick textile units which are not viable;

(b) what is the number of textile mills of NTC which can never be viable;

(c) what are the details of the amount sanctioned and spent for the revival of the sick textile mills, state-wise; and

(d) what is the amount of losses at present of NTC mills and what is the total accumulated losses of the NTC?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Government have approved a Turn Around Strategy for NTC mills involving modernisation, restructuring and rationalisation of surplus workforce through the Voluntary Retirement Scheme. Voluntary Retirement Scheme will also be offered to the officers, staff and workers of such chronically sick mills, which have no possibility of viability and which may have to be closed down or merged with adjacent units to ensure viability. The question of closure or retention of individual mills of NTC will depend on the impact on viability of labour rationalisation now being done through Voluntary Retirement Scheme and other relevant factors. Government have approved an investment of Rs. 689 crores for implementation of Voluntary Retirement Scheme, Rs. 533 crores for modernisation of NTC mills, Rs. 200 crores for improving the liquidity of NTC mills and Rs. 50 crores for retraining and rehabilitation of workers proceeding on Voluntary Retirement Scheme. However, no state-wise allocation has been made in this regard.

(d) The accumulated losses of NTC mills upto 31st March, 1992 were Rs. 2324 crores. During the period April-November, 1992, NTC mills suffered provisional net loss of Rs. 314 crores.

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

788. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत चलने वाली कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 5.33 करोड़ रुपए की एक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) जनवरी, 1993 के अन्त तक कुल कितनी मिलों में आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया गया था और इस मद के अन्तर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण पर लगभग 533 करोड़ रु० की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के 56 प्रस्तावों की पहचान की गई है जिनमें से 40.07 करोड़ रु० के परिव्यय के 3 प्रस्तावों को पहले से ही क्रियान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षमता

789. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम और बी० आई० सी० की सूती मिलों के 1994-95 तक अर्थक्षम हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में गत वर्ष किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (ग) सरकार ने अगस्त, 1992 में एन टी सी और टी आई सी वस्त्र मिलों के लिये एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें

आधुनिकीकरण, पुनः निर्माण और श्रमिकों के स्वैच्छिक सुव्यवस्थीकरण की परिकल्पना की गई है ; ऐसी आशा है कि ग्रामीण सुधार नीति के कार्यान्वयन के पश्चात एन टी सी मिलें और बी आई सी की वस्त्र मिलें आर्थिक रूप से अर्थक्षम हो जाएंगी।

Decline in Cloth Production

790. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the total cloth production in the country in all the three sectors namely mill, powerloom and handloom during the years 1990-91. 1991-92 and 1992-93;

(b) whether the cloth production has registered a sharp decline since the last year;

(c) whether it is a fact that the Textile Industry has failed to take advantage of the concessions extended by Government if so, what are the reasons therefore; and

(d) what steps are being taken to augment textile production which is a big area for exports as well as employment in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) The total cloth production in the country in all the three sectors namely mill, powerloom and handloom during the years 1990-91, 1991-92 and 1992-93 are;

(Mill. Sq. Mtrs)

Year	Mill Sector	Power-loom Sector	Hand-loom Sector
1990-91	2589	16044	4295
1991-92	2376	16089	4123
1992-93 (Estimate)	2255	16630	4255

(b) In 1991-92 nominal fall in production has been registered.

(c) No, Sir.

(d) Government have taken various steps to augment textile production such as:

1. Restriction of creation and expansion of capacity has been removed subject only to locational guidelines.

2. Requirement of licencing has been done away with.

3. Measures are taken to ensure availability of raw material for the industry through policy intervention whenever necessary.

4. Textile Machinery can be imported and duty on such machinery has already been reduced.

उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र का विकास

791. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान हथकरघों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश से किस-किस प्रकार के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हथकरघों के विकास के लिए वास्तव में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकट स्वामी): (क) गत दो वर्षों के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में ऊनी हथकरघा विकास परियोजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, निःसहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना, जनता कपड़ा योजना आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य को हथकरघों के विकास के लिए जारी की गई राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि लाखों में
1989-90	3191.32
1990-91	4499.84
1991-92	3769.42

उत्तर प्रदेश में तकलों का वितरण

792. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तकलों को वितरित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है